भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 460

दिनांक 06 **फरवरी**, 2023

तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाया जाना

460 **श्री आर. गिरिराजन** :

श्री एस. कल्याणसुन्दरम:

श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की तेल और गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए और आयातित तेल पर निर्भरता कम करने के लिए अपने तेल उत्पादन और अन्वेषण की मात्रा को दोगुना करने की कोई योजना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश द्वारा वर्ष 2018 से अब तक वर्ष-वार कितने कच्चे तेल का आयात किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा एथेनाल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री

(**श्री रामेश्वर तेली**)

(क): सरकार खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) के तहत 2.08 लाख वर्ग कि.मी. के अन्वेषण रकबे पहले ही प्रदान कर चुकी है और अतिरिक्त 2.57 लाख वर्ग कि.मी. के रकबों के लिए बोली दौर शुरू कर दिए गए हैं। वर्ष 2023-24 में 32.5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) के स्तर पर कच्चे तेल का उत्पादन करने की योजना बनाई गई है।

(ख) वर्ष 2018 से दिसंबर 2022 तक आयात किए गए कच्चे तेल का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वित्त वर्ष	मात्रा (एमएमटी)
2018-19	226.5
2019-20	227.0
2020-21	196.5
2021-22 (पी)	212.4
2022-23 (अप्रैल-दिसंबर) (पी)	172.4

स्रोत: तेल कंपनियां

पी: अनंतिम

(ग): सरकार ने देश में एथेनॉल का उत्पादन और उपयोग बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें संबंधित बीआईएस मानक पूरे करने की शर्त पर पेट्रोरसायन रूट सहित शीरे के अलावा सैल्यूलॉसिक और लिग्नोसैल्यूलॉसिक जैसी अन्य गैर खाद्य फीड स्टॉक सामग्रियों जैसे कपास के डंठल, गेहूं का भूसा, चावल का भूसा, खोई, बांस आदि से उत्पादित एथेनॉल की अधिप्राप्ति की अनुमति देना; एथेनॉल के उत्पादन हेतु गन्ना और खाद्यान्नों (मक्का और भारतीय खाद्य निगम के पास रखे चावल का अधिशेष स्टॉक) का उपयोग करने की अनुमति देना; एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2017-18 से एथेनॉल के वर्धित एक्स-मिल मूल्य सहित एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत एथेनॉल की अधिप्राप्ति के लिए प्रशासित मूल्य व्यवस्था; ईबीपी कार्यक्रम के लिए एथेनॉल पर जीएसटी की दर कम करके 5% करना; मिश्रण के लिए सभी राज्यों में एथेनॉल की अबाधित ढुलाई हेतु उद्योग (विकास व विनियमन) अधिनियम में संशोधन, एथेनॉल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और उसके विस्तार हेतु ब्याज इमदाद योजनाएं, एथेनॉल की कमी वाले राज्यों में समर्पित एथेनॉल संयंत्रों के लिए 131 परियोजना प्रस्तावों के साथ दीर्घकालिक ऑफ टेक करार (एलटीओए) पर हस्ताक्षर करना आदि शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण वर्ष 2014 में 1.53 प्रतिशत से बढ़कर एथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2021-22 में 10 प्रतिशत से अधिक हो गया है।

****